ग्राम स्वराज अभियान के 9 लक्ष्य तथा सतत विकास के 17 बिंदुओं में से एक भी नहीं हो सके पूरे

ग्रामीण विकास के लिए केन्द्र सरकार ने निर्धारित किए हैं लक्ष्य और बिन्दु

नवभारत न्यूज

पन्ना 9 नवंबर। महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज के माध्यम से विकास का सपना देखा था केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज के तहत 9 लक्ष्य निर्धारित किये गये थे जिनमें से आज तक एक भी लक्ष्य पूरे नहीं हो सके। कारण सिर्फ यही रहा कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास के चाहे निर्वाचित जनप्रतिनिधि रहे हो या शासकीय विभागीय अमला रहा हो। सबका लक्ष्य ग्रामीण विकास नहीं बल्कि स्वयं का विकास रहा है। इसी कारण ग्राम स्वराज का सपना चकनाचूर हो गया।

निर्धारित 9 थीम का लक्ष्य केवल दिखावा साबित

राष्ट्रीय ग्राम स्वाराज अभियान के लक्ष्यों को पूरा करने के लिये 9 थीम निर्धारित किये गये थे। जिनमें गरीबी मुक्त गांव, स्वस्थ गांव, बाल हितैषी गांव, जल पर्याप्त गांव, स्वच्छ और हरित गांव, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाला गांव, सामाजिक रूप से संरक्षित गांव, सुशासन वाला गांव, महिला हितैषी गांव थीम शामिल थी। इसके लिये 17 बिन्दुओं का सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जिनमें गरीबी के सभी रूपों को हर तरह से समाप्त करना, भुखमरी को समाप्त करना, सभी उम्र के लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा एवं स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना, समावेशी शिक्षा और सभी को समान अवसर, लैंगिक समाना से सशक्तिकरण, सभी के लिये स्वच्छ पानी की उपलब्धता, सभी के लिये सस्ती टिकाऊ एवं आधुनिक उर्जा तक पहुच सुनिश्चित करना, औधोगिकीकरण एवं नवाचार को बढ़ावा देना, शहरों एवं मानव वस्तियों को समावेशी, सुरक्षित एवं टिकाऊ बनाना, जंगलों का स्थायी प्रबंधन, भूमि संरक्षण एवं जैव विविधता के नुकसान को रोकना आदि लक्ष्य निर्धारित किये गये थे। इन लक्ष्यों एवं थीमों को देखने से लगता है कि गांवों के विकास के लिये सरकारों ने बेहतर योजनाओं की परिकल्पना की थी किन्तु दुर्भाग्य यह रहा कि कागजों तक ही क्रियान्यन हो पाया। जमीन में योजनाओं का असर कहीं भी दिखाई नहीं दिया।

संविधान के अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों सहित आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिये योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये राज्यों को अधिकार दिये गये हैं। इसके तहत ग्राम पंचायतों के लिये पंचायतें, जनपद स्तर के लिये जनपद पंचायत एवं जिला स्तर की परियोजनाओं के लिये जिला पंचायतों को अनुमोदन के लिये प्रावधान बनाये गये। इसके तहत पंचायत स्तर पर जीपीडीपी, ब्लाक स्तर पर बीपीडीपी, जिला स्तर पर डीपीडीपी तैयार करने के

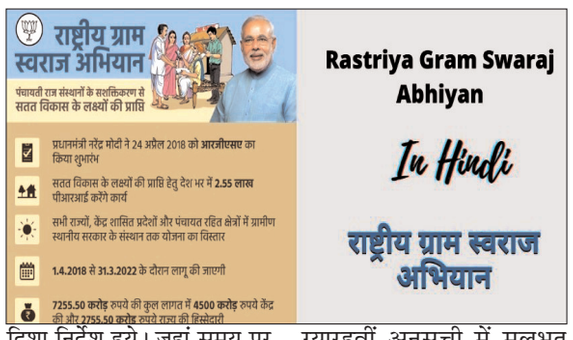

दिशा निर्देश हुये। जहां समय पर योजनाओं का खाका तैयार होता रहा किन्तु उसका क्रियान्वयन कारणो से आज तक नहीं हो पाया। जिस तरह से व्यापक रूप से प्रावधान किये गये वे केवल कागजों तक ही सिमट कर रह गये। कभी योजनाओं का नाम बदला तो कभी अन्य संशोधन हुये। बावजूद इसके जमीन में कोई असर आज तक नहीं दिखाई दिया।

11 वीं अनुसूची में सूचीबद्ध मामले:- ज्ञात हो कि ग्यारहवीं अनुसूची में मूलभूत कार्य एवं कल्याण से संबंधित मामलों को सूचीबद्ध किया गया था। जहां मूलभूत मामलो में पेयजल, सड़क, पुलिया, जलमार्ग, संचार, बिजली, अस्पताल, औषधालय, स्वच्छता, कृष, भूमिसुधार, सिंचाई, पशुपालन, डेयरी, मछली पालन, लघु वनोपज, बाजार मेला आदि को शामिल किया गया था। जबकि कल्याण सूची में ग्रामीण आवास, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, सांस्कृतिक गविविधियां, परिवार कल्याण, महिला बाल विकास, कमजोर वर्गों का कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, लघु उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, खादी ग्राम एवं कुटीर उद्योग को शामिल किया गया था।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का उदय और संचालन:- सूचीबद्ध मामलों को जमीन में उताने के लिये वर्ष 2016-17 में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की शुरूआत हुई। क्रियान्वयन के लिये दिशा निर्देश जारी हुये। आगे चलकर राष्ट्रीय गाम स्वराज अभियान को संशोधित किया गया। 15वें वित्त आयोग के समय एक बार फिर संशोधन किया गया। इस तरह से समय-समय पर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान में संशोधन तो होते चले गये। जिसके अनुसार ग्राम पंचायतों से लेकर जनपद व जिला पंचायत स्तर की योजनायें भी तैयार होती चली गई। किन्तु उन योजनाओं का क्रियान्वयन जमीन में नहीं हो पाया।

नहीं मिट पाई गांवों से गरीबी

पहली थीम एवं पहले लक्ष्य को ही देखा जाय तो गांवों से गरीबी आज तक नहीं हट पाई। गांवों में आज भी गरीबी बुरी स्थिति में पहुच चुकी है। भले ही पोषण के नाम पर कुछ लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पेट भरने के लिये सस्ते दर पर खाद्यान्न उपलब्ध हो रहा हो। किन्तु गरीबी को पूरी तरह से गांवों के भगाने को जिस तरह से लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिस तरह से कल्पना की गई थी वह सफल नहीं हो पाई। क्रियान्वयन में कमियां थी या सिस्टम में कमियां थी। कुछ न कुछ तो था जिसके चलते गरीब का आज भी चुनौती के रूप में दिखाई दे रही है। गांव के गरीब का हाल यह है कि वह बीमार होता है तो दवाई के लिये पैसे नही होते। गांव से बाहर जाने के लिये उसके पार किराये का पैसा नहीं होता। वह मजदूरी करने के लिये पलायन करता है। उसे बेहतर शिक्षा भी नही मिल पाती। लिहाजा यह कहा जा सकता है कि गरीबी हटाने की चिन्ता तो हुई किन्तु उसे प्रभावी तरीके से समाप्त करने के सफल प्रयास नही हो पाये। वहीं दूसरी ओर अधोसंरचना एवं विकास की बात की जाय तो वहां का भी यही हाल रहा। कागजों में योजनायें बजट उपलब्ध हुआ, किन्तु जमीन में वह नहीं उतर पाया। गुणवत्ता एवं समय सीमा का कोई ध्यान नहीं दिया गया करोड़ों की राशि कुछ ही वर्षो में एक-एक पंचायतों में पानी की तरह बहा दी गई। किन्तु जहां तस्वीर पंचायतों की चमकती हुई दिखनी चाहिये वहां वह आज भी अंधेरे में डूबी हुई दिखाई देती है। इसलिये सवाल यह उठता है कि इस तरह की योजनायें कब तक बनती रहेगी। जहां लंबे चैड़े भारी भरकम उपदेशों के साथ कार्यक्रमों का साहित्य तो तैयार हो जाता है। किन्तु वह जमीन में नहीं उतर पाता।

सिद्धांत का सीएमओ पद पर हुआ चयन

नवभारत न्यूज

पन्ना 9 नवंबर। नगर के होनहार युवक सिद्धांत जैन डी.के. जैन, का चयन मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा में मुख्य नगरपालिका अधिकारी पद पर हुआ है। सिद्धांत ने अपनी इस उपलब्धि पर जीरो सेवा समिति अध्यक्ष कमलेश जैन ने समिति की ओर से बधाई संदेश जारी करते हुए कहा सिद्धांत जैन की यह सफलता देवेंद्रनगर के हर विद्यार्थी के लिए प्रेरणा है।

देवेंद्रनगर से नायाब हीरे निकलकर देशभर में प्रशासनिक, स्वास्थ्य और तकनीकी सेवाओं में नाम कमा रहे हैं, लेकिन नगर में उच्च शिक्षा की सुविधाएं आज भी शून्य हैं। चालीस वर्षों से नगर केवल कला संकाय में स्नातक तक सीमित है कृषि न विज्ञान, न वाणिज्य, न स्नातकोत्तर शिक्षा।

यह किसी भी सरकार के लिए शर्मनाक स्थिति है। उन्होंने कहा कि 75 प्रतिशत छात्राएँ उच्च शिक्षा के अवसरों के अभाव में अपने सपनों को अधूरा छोड़ने पर विवश हैं। बीते दो दशकों में देवेंद्रनगर के छात्र-छात्राएँ लगातार प्रदेश की प्रवीण्य सूची में स्थान प्राप्त कर नगर का नाम रोशन कर रहे हैं, परंतु सरकार की अकर्मण्यता और संवेदनहीनता ने इस प्रतिभाशाली नगर को विकास की मुख्यधारा से अब तक अलग रखा है।

फसलों को चौपट कर रही नीलगाय बनी किसानों के लिये परेशानी का सबब

नवभारत न्यूज

पन्ना 9 नवंबर। जिले में खासकर अजयगढ़ तहसील के कुछ गांवों में कृषि करना किसानों के लिये बड़ी चुनौती का सबब नीलगायों के कारण बन चुका हैं। एक तरफ सरकार कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिये दावा करती है।

किसानों की चिंता को लेकर सरकार कई बार कृषि कर्ज माफ करने या अन्य छूटें विद्युत बिल हाफ करने जैसी योजनाओं को तो क्रियान्वित करने के लिये पहल करती है पर यहां किसानों के लिये सबसे बड़ी समस्या कृषि उत्पादन में नीलगायों के द्वारा बन चुकी है। पन्ना जिले में टाईगर रिजर्व तो जहां जानवरों को लेकर बफर जोन निर्माण की स्कीम के तहत रकवा बढ़ाने के लिये हर समय अपने प्रयास जारी रखते हैं। वहीं किसानों के खेतों में नीलगाय इस तरह से धावा बोलती हैं कि एक ही दिन में में किसान की फसल तबाह हो जाती है। इन हालातों में कृषि लाभ का व्यवसाय कैसे बने जो अपने आप मे चिंताजनक सवाल बन चुका है। किसान किस किस खेत में पहरा देगा, कैसे बचाए खेत में फसलों को जहां सैंकड़ों की संख्या में नीलगायों का झुंड खेतों में धावा बोलती हैं। इन हालातों में किसान के लिये फसल उत्पादन असंभव की स्थिति बन चुकी है। कृषि छोड़कर दूसरा व्यवसाय भी किसान के लिये आसान नहीं।

विषम परिस्थितियों मे जहां प्रकृति के हालात दिनों दिन भारी पड़ रहे हैं कभी बाढ़ तो कभी सूखे के हालात तो कहीं तुषार फसलों के लिये उत्पादन में एक बड़ी समस्या तो थी ही वहीं दूसरी तरफ अगर फसल किसी तरह से खेतों में दिखी तो नीलगायों के कारण बच नहीं पा रही क्योंकि मप्र में चकबंदी तो हुयी नहीं जिस कारण से हर कृषक के खेत अलग अलग क्षेत्र में गांवों में ही होते हैं। इन परिस्थितियों मे किसान किन किन खेतों में सुरक्षा को लेकर इंतजामात करे हालात बेकाबू हो चुके हैं, नीलगायों के कारण किसान फसल उत्पादन करने में पूर्णत: अपने आपको अक्षम मान रहा है। सरकार इस समस्या को नजरअंदाज किए हुए हैं। कई बार किसानों ने नीलगायों से फसल के नुकसान की बात पहुंचाने का प्रयास किया पर इस पर प्रशासन के द्वारा आज दिनांक तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए क्या किसानों के खेतों में नीलगायों को विचरण करने के लिये इस तरह की खुली छूट देने का अधिकार प्रशासन को या जंगली जानवरों की सुरक्षा करने वाले जो किसान पर शिकार करने का आरोप लगाकर उसे आरोपी बनाते हैं तो क्या फसल नुकसान करने में यह विभाग अपने आपको किसानों के लिये हितकारी है। कैसे हो किसानों फसल की सुरक्षा नीलगाय बनी समस्या।

भावांतर योजना में 4036 रुपए प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी

पन्ना 9 नवंबर। भावांतर योजना 2025 अंतर्गत सोयाबीन विक्रेता किसानों के लिए 9 नवम्बर को 4036 रुपए प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी किया गया है। यह मॉडल रेट उन किसानों के लिए है, जिन्होंने सोयाबीन की अपनी उपज मंडी प्रांगणों में विक्रय की है। इस मॉडल रेट के आधार पर ही भावांतर की राशि की गणना की जाएगी।

सीएमएचओ ने किया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पवई का औचक निरीक्षण

नवभारत न्यूज

पन्ना 9 नवंबर। दिनांक 8 नवंबर को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पन्ना डॉ आर पी तिवारी के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पवई का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान ड्यूटी रोस्टर अनुसार कर्मचारियों की उपस्थिति, जनरल वार्ड, लेबर रूम सहित सभी शाखाओं का निरीक्षण किया गया एंव वार्डो में भर्ती मरीजों से संबाद

कर प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर चर्चा की गई। सीएमएचओ ने सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली एंव निर्देश दिए कि 2 दिवस में अधिकतम शिकायतों को संतुष्टिपूर्वक बंद कराये। प्रत्येक मंगलवार एंव शुक्रवार को आयोजित वीएचएसएनडी में सुपरविजन हेतु ब्लॉक स्तरीय टीम एवं सेक्टर सुपरवाइजर को निर्देश दिए गए। शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने एवं कार्य न करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करने के भी निर्देश दिए गए।

पुलिस लाइन पन्ना में आयोजित हुआ एक दिवसीय स्वास्थ्य परीक्षण शिविर

नवभारत न्यूज

पन्ना 9 नवंबर। पुलिस अधीक्षक पन्ना श्रीमती निवेदिता नायडू के निर्देशन एवं पहल पर आज दिनांक 09 नवम्बर को पुलिस लाइन पन्ना में एक दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों एवं उनके परिजनों के स्वास्थ्य परीक्षण के साथ-साथ उन्हें आपातकालीन स्वास्थ्य सहायता के प्रति जागरूक करना था।

इस स्वास्थ्य शिविर का आयोजन डॉ राय हॉस्पिटल सागर के चिकित्सकों के सहयोग से किया गया। शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा पुलिसकर्मियों एवं उनके परिजनों का ई.सी.जी., ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल, सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण आदि किया गया तथा आवश्यकता अनुसार उन्हें चिकित्सकीय परामर्श प्रदान किया गया। कार्यक्रम के दौरान चिकित्सकों द्वारा उपस्थित पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सी.पी.आर. का प्रायोगिक प्रशिक्षण भी दिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि आकस्मिक परिस्थितियों जैसे हृदयगति रुकने की स्थिति में सी.पी.आर. देने की सही तकनीक से किसी व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। प्रशिक्षण के दौरान चिकित्सकों ने डेमो के माध्यम से सी.पी.आर. की प्रक्रिया को समझाया और सावधानियों की जानकारी दी उक्त शिविर में डॉ राय हॉस्पिटल मकरोनिया सागर से डॉ. प्रतीक (एम डी मेडिसिन), डॉ संतोष राय (जनरल सर्जन), डॉ अखिलेश जैन (पल्मोनरी सर्जन), डॉ मनीष (प्लास्टिक सर्जन), डॉ नीलेश (आर्थो), डॉ श्रीधाम (न्यूरो सर्जन) एवं सहयोगी स्टॉफ उपस्थित रहा जिन्होंने संबंधित उचित जांच कर आवश्यक परामर्श दिए। इस अवसर पर एसडीओपी पन्ना एस पी सिंह बघेल, डीएसपी अजाक राजेंद्र मोहन दुबे, रक्षित निरीक्षक पन्ना खिलावन सिंह कंवर, यातायात थाना प्रभारी नीलम लक्ष्यकार, थाना प्रभारी कोतवाली रोहित मिश्रा, एवं पुलिस विभाग के लगभग 200 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी एवं उनके परिवारजन उपस्थित रहे।

सरकारी धान खरीदी चालू न होने से ओने-पोने दामों में किसान बेचने को मजबूर

नवभारत न्यूज

गुनौर/पन्ना 9 नवंबर। वर्तमान में धान की फसल पककर तैयार हो गई है एवं धान की बहुत सारी कटाई भी हो गई है। रोजाना गुनौर में हजारो क्विंटल धान बिकने आ रही है।

जिसे आज की तारीख में गल्ला व्यापारी 1500 रुपए से लेकर अधिकतम 1900 रुपया प्रति क्विंटल खरीद रहे हैं। इसी प्रकार कई व्यापारी किसान भी है जिन्होंने पहले से धान खरीदने के लिए पंजीयन करा लिया है वह खरीदकर भंडारण कर रहे हैं। यह स्थिति इसलिए है क्योंकि समर्थन मूल्य पर शासन द्वारा खरीदी जाने वाली धान की खरीदी चालू नहीं हुई है। जबकि जो वास्तविक सीमांत किसान है उसे धान बेचकर दूसरी फसल की लागत के लिए तुरंत आवश्यकता है इसलिए वास्तविक जरूरत मंद खेती पर निर्भर किसान को 500 रु प्रति क्विंटल से लेकर 900 रुपया प्रति क्विंटल तक का घाटा शासन के किसान हितैषी जिम्मेदारों की उदासीनता के कारण उठाना पड़ रहा है।

शासन के समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी जहां गल्ला व्यापारियों एवं किसान व्यापारियों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है वहीं वास्तविक किसान के साथ शासन की समर्थन मूल्य वाली योजना धोखा प्रतीत हो रही है।

मौसम परिवर्तन का असर सर्दी की सुस्त शुरूआत से ठंडे पड़े गर्म कपड़ों के बाजार

नवभारत न्यूज

पन्ना 9 नवंबर। जलवायु परिवर्तन का असर अब आम जीवन के हर पहलू पर दिखने लगा है। नवंबर का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन मौसम में अभी भी गर्माहट बरकरार है।

दिन का पारा 30 डिग्री के आसपास घूम रहा है, जिसके चलते सर्दियों के कपड़ों का बाजार इस बार ठंडा पड़ा है। शहर के बाजारों में तिब्बती व्यापारी अपनी पारंपरिक दुकानें सजा चुके हैं, परंतु ग्राहकों की कमी के कारण बिक्री रफ्तार नहीं पकड़ पा रही है। पूर्व मे जहां नवरात्रि के बाद ठंडक बढ़ने लगती थी और अक्टूबर से ही गर्म कपड़ों की मांग बढ़ जाती थी।

सामूहिक विवाह कार्यक्रम में हर विवाह का होगा पंजीयन

नवभारत न्यूज

पन्ना 9 नवंबर। देव उठनी एकादशी के साथ ही विवाहों का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। विवाहों के शत प्रतिशत पंजीयन के लिए कलेक्टर्स को निर्देश जारी किए गए हैं।

यह योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग की एक सराहनीय पहल है। इससे विवाहों का शत प्रतिशत पंजीयन हो सकेगा, जिससे भविष्य में दंपत्ति को कानूनी अड़चनों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश विवाह रजिस्ट्रेशन नियम 2008 के अनुसार राज्य के भीतर भारत के नागरिकों के बीच किसी भी विधि या रूढ़ि के अधीन सत्यापित किए गए विवाह का पंजीयन किया जाता है। विवाहों का पंजीयन नहीं होने पर विशेष तौर पर महिलाओं को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पति की मृत्यु के बाद उनको मिलने वाले स्वत्वों के भुगतान आदि में परेशानी होती है। विवाह पंजीयन के लक्ष्य को शत प्रतिशत प्राप्त करने हेतु प्रदेश के समस्त कलेक्टरों का ध्यान आकृष्ट किया गया है। जिलों में आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री निकाह योजना एवं अन्य सामूहिक विवाहों में कार्यक्रम स्थल पर ही विवाह प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने का सुझाव दिया गया है। सामूहिक विवाह कराने वाली सभी संस्थाओं से जागरूकता बढ़ाने मुहिम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की गई है।

अब घर बैठे बनेगा जीवन प्रमाण पत्र

नवभारत न्यूज

पन्ना 9 नवंबर। हर साल नवम्बर माह में पेंशनरों को अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र बैंक में देना पड़ता है।

इसी के आधार पर उनकी पेंशन आगे चालू रहती है, लेकिन इस नियम के चलते ऐसे बुजुर्ग पेंशनरों को दिक्कत झेलनी पड़ती है, जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं या फिर चलने-फिरने में असमर्थ हैं। पेंशनरों की इसी समस्या को देखते हुए भारतीय डाक विभाग ने पेंशनधारकों के लिए एक सुविधाजनक सेवा की शुरुआत की है। अब पेंशनधारकों को अपने जीवन प्रमाण बनवाने के लिए बैंकों या सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। डाक विभाग ने इस कार्य के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सुविधा प्रारंभ की है, जिसके तहत अब डाक विभाग डूर स्टेप सर्विस के माध्यम से स्वयं पेंशनधारक के घर पहुंचकर जीवन प्रमाण पत्र तैयार करेगा। इस सुविधा के लिए मात्र 70 रूपए का शुल्क निर्धारित किया गया है। यह सेवा न केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए हित भरी है, बल्कि उनके लिए एक बड़ी सहूलियत भी है। तैयार होने के बाद डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र स्वचालित रूप से संबंधित पेंशन प्रदाता संस्थान तक ऑनलाइन माध्यम से पहुंच जाता है।

भाजपा नेता एवं प्रतिष्ठित व्यवसायी शिरीष अग्रवाल कांग्रेस में शामिल

नवभारत न्यूज

पन्ना 9 नवंबर। क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यवसायी शिरीष अग्रवाल ने देशहित एवं विचारधारा से प्रेरित होकर गत दिवस को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।

यह कार्यक्रम संस्कार गार्डन, देवेंद्रनगर में आयोजित किया गया, जहाँ गुन्नौर प्रभारी अशोक मिश्रा एवं निर्वाचन प्रभारी राजबहादुर पटेल की उपस्थिति में श्री अग्रवाल को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने उनका गुलाल एवं पुष्पमाला पहनाकर और शाल-श्रीफल भेंट कर हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने देशहित एवं जनता की सेवा की भावना से प्रेरित होकर कांग्रेस पार्टी की नीतियों पर विश्वास जताया है और आने वाले समय में जनसेवा को प्राथमिकता देंगे।

बिना भवन के कागजों में संचालित हो रहे दूरवर्ती अध्यन केन्द्र

कुकुरमुत्तों की तरह कागजों में संचालित हैं दर्जनों दूरवर्ती केंद्र, नकल के नाम पर होती है मोटी रकम वसूली

नवभारत न्यूज

पन्ना 9 नवंबर। जिले भर में संचालित दूरवर्ती प्राईवेट कॉलेज स्टडी सेंटर की आड़ में गरीब छात्रों से मोटी फीस भी वसूल कर रहे हैं। जिले अधिकांश दूरवर्ती अध्ययन केन्द्र चाय पान के ठेलों तो कहीं स्टेशरी दुकानों तो कहीं पर दस बाई दस के कमरे में जहां पर सिर्फ आफिस की कुर्सी टैबिलें रखी हैं पढ़ाई कभी नही होती। केवल बुकिंग आफिस के नाम पर उक्त छोटे कमरे से जाने जाते हैं।

मालूम हो कि जिले में प्राईवेट कॉलेजों का यह गोरखधंधा करीब पिछले दस साल से चल रहा है, लेकिन आज तक इन प्राइवेट कॉलेज पर शिकंजा कसने वाला कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं है। तथा राजनेताओं का पूरा संरक्षण प्राप्त है। जिसे देखकर कहा जा सकता है कि शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों द्वारा ऐसे प्राईवेट कॉलेजों को लूटने के लिए खुली छूट दे कर रखी गई हैं। जिसके बदले ऐसे जिम्मेदार नुमांइदों का भी सालाना कमीशन बंधा होता है।

इन विवि से संबंद्धता की भरमार:- ज्ञात हो कि शहर मे जबलपुर के महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय से स्टडी सेंटर की संबद्धता लेकर निजी कॉलेज संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा पंजाब टेक्निकल विश्वविद्यालय, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट समेत अन्य दूसरे जिले व प्रदेश के विश्वविद्यालयों से स्टडी सेंटर की संबद्धता लेकर निजी कॉलेज संचालित हो रहे हैं। साथ ही नियमित कक्षाओं का दिखावा कर ऐसे कॉलेज छात्रों से मोटी फीस भी वसूल कर रहे हैं। यहीं नही ऐसे कालेज में पढ़ने वाले छात्रों की डिग्री भी तीन साल क बजाये चार साल में पूरी हो रही है।

पन्ना विवि के क्षेत्र में दूसरे की संबद्धता भी नियम विरूद्ध:- बताया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार किसी भी विश्वविद्यालय के क्षेत्र में किसी अन्य दूसरे विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेज संचालित नहीं हो सकते। इसके बावजूद जिले में न केवल दूसरी जिलों के विश्वविद्यालय सम्बद्ध प्राईवेट कालेज संचालित हैं। इस नियम के तहत सागर विश्वविद्यालय क्षेत्र में दूसरे विश्वविद्यालय से सम्बद्ध रेग्युलर डिग्री कोर्स संचालित करना ही प्राथमिक तौर पर गलत है।

स्टडी सेंटर की आड़ में चल रहा गोरख धंधा

इस मुद्दे पर उच्च शिक्षा जगत के लोगों द्वारा बड़े स्पष्ट तरीके से आमतौर पर कही जाती है कि जिले में जितने भी प्राईवेट कालेज हैं, उन्हें संबंधित विश्वविद्यालय के दूरवर्ती शिक्षा केन्द्र से स्टडी सेंटर संचालित करने की संबद्धता प्राप्त है। जिसकी आड लेकर ऐसे प्राइवेट कालेज न केवल रेग्युलर डिग्री कोर्स चला रहे हैं वरन छात्रों से मोटी रकम वसूल करने के बाद भी उन्हें धोखा दे रहे हैं। यहां स्टडी सेंटर के मायने बता दें कि किसी भी विश्वविद्याय के दूरवर्ती केन्द्र से स्टडी सेंटर की संबद्धता होने के अर्थ हैं कि विश्वविद्यालय के उक्त केन्द्र द्वारा संचालित दूरवर्ती कोर्स में छात्रों को प्रवेश देना और परीक्षा से पहले पंद्रह दिन की कक्षा और फिर विश्वविद्यालय द्वारा घोषित परीक्षा कार्यक्रम में संबंधित अभ्यर्थी को दूरवर्ती केन्द्र यानि एक तरह से प्राइवेट कोर्स की डिग्री प्राप्त होती है।

गाइडें रखकर निजी भवनों में तालाबंदी कर होती है खुलेआम नकल

जो छात्र कहीं परीक्षा में पास न होता हो और पढ़ने में सबसे कमजोर हो या पढ़ने में कोई मेहनत न करते हुए सिर्फ नकल से पास करना चाहता हो तो इसके लिये जिले भर में सैंकड़ों की संख्या में खुले कागजी दूरवर्ती केंद्र वरदान साबित हो रहे है। हर वर्ष दूरवर्ती केंद्रों के संचालकों द्वारा प्रशासनिक एवं विभागीय सांठ गांठ कर प्रायवेट भवनों जिसमें धर्मशालाएं तथा अन्य अशासकीय भवन शामिल हैं। वहां पर परीक्षा सेंटर कराकर मेन गेट का ताला बंद कर खुलेआम गाइडें धरकर नकल करा कर परीक्षार्थियों को पास कराया जाता है। इसी नकल सुविधा के नाम पर छात्रों को मनमाना फीस देने के लिये मजबूर किया जाता है।